झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची

सिविल रिट याचिका सं० - 5356/2023

आलोक कुमार डेंगी, उम्र लगभग 42 वर्ष, पिता श्री बिजय कुमार सिंह, निवासी ग्राम - भलुहार, डाकघर - चंगाई, थाना - रोशनगंज, जिला - गया, बिहार।

..... **याचिकाकर्ता**

-बनाम-

1. झारखण्ड राज्य.
2. खान आयुक्त, झारखंड, कार्यालय, नेपाल हाउस, डाकघर+थाना - डोरंडा, जिला - रांची (झारखंड)।
3. उपायुक्त, चतरा, डाकघर+थाना - चतरा, जिला - चतरा (झारखंड)।
4. जिला खनन पदाधिकारी, चतरा, डाकघर+थाना-चतरा, जिला - चतरा (झारखंड)।

..... **प्रतिवादी**

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्रीमान सुजीत नारायण प्रसाद

माननीय न्यायमूर्ति श्रीमान नवनीत कुमार

याचिकाकर्ताओं की ओर से: श्री शाहिद खान, अधिवक्ता

श्री राकेश कुमार, अधिवक्ता

प्रतिवादियों की ओर से: श्री सुरभि, ए.सी टू ए.ए.जी-II

<u>मौखिक जजमेंट/निर्णय</u>

<u>03/दिनांक: 29 नवंबर, 2023</u>

<u>न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद</u>

1. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका खान आयुक्त पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा पुनरीक्षण वाद संख्या 65/2022 में पारित दिनांक 28.03.2023 के आदेश को रद्द करने के लिए दायर की गई है, जिसके तहत मौजा-लोढिया, डाकघर-प्रतापपुर, खाता संख्या 21, प्लाट संख्या

118(पी) में पत्थर के खनन के लीज को समाप्त करने के सक्षम प्राधिकारी के निर्णय में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया गया है।

2. रिट याचिका में की गई दलील के अनुसार मामले के संक्षिप्त तथ्य, जिन्हें गिनाना आवश्यक है, इस प्रकार हैं:

उपायुक्त, चतरा द्वारा दिनांक 04.03.2016 को आदेश द्वारा खनन पट्टा विलेख निष्पादित किया गया था, जिसे संबंधित विभागों से सभी आवश्यक मंजूरी प्राप्त करके 29.03.2016 को विधिवत पंजीकृत किया गया था। जिला खनन पदाधिकारी, चतरा ने ज्ञापांक 356 दिनांक 29.03.2022 के तहत एक आदेश जारी कर रिट याचिकाकर्ता को खनन लीज के संबंध में अतिरिक्त रॉयल्टी के रूप में 6,73,031/- रुपये जमा करने को कहा था। जिला खनन पदाधिकारी, चतरा द्वारा पत्र दिनांक 21.04.2022 के तहत उक्त अतिरिक्त रॉयल्टी के भुगतान के संबंध में एक अनुस्मारक भी दिया गया था। इसके बाद, अतिरिक्त रॉयल्टी का भुगतान करने के लिए पुनः एक और अनुस्मारक पत्र दिनांक 18.06.2022 के तहत दिया गया था।

रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि प्रासंगिक समय पर याचिकाकर्ता गंभीर रूप से बीमार था और दुर्घटना का शिकार हो गया था, इसलिए उसने उप खनन पदाधिकारी से पत्र दिनांक 06.08.2022 के तहत अतिरिक्त रॉयल्टी का भुगतान करने के लिए समय देने का अनुरोध किया था। इसके बाद रिट याचिकाकर्ता ने पत्र दिनांक 22.10.2022 के तहत उप खनन पदाधिकारी, चतरा से पुनः समय मांगा कि अतिरिक्त रॉयल्टी की राशि का भुगतान 10.11.2022 तक कर दिया जाएगा।

जिला खनन अधिकारी, चतरा ने पत्र संख्या 1076 दिनांक 02.11.2022 के माध्यम से याचिकाकर्ता को सूचित किया कि लीज समय से पहले रद्द कर दिया गया है और रिट याचिकाकर्ता को 9,28,039/- रुपये जमा करने का निर्देश दिया।

रिट याचिकाकर्ता ने निर्धारित तिथि के बाद उप खनन पदाधिकारी, चतरा द्वारा मांगे गए ब्याज सहित अतिरिक्त रॉयल्टी की राशि जमा कर दी।

रिट याचिकाकर्ता ने लीज की समाप्ति से व्यथित होकर प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष संशोधन मामला संख्या 65/2022 प्रस्तुत किया,

जिसे दिनांक 28.03.2023 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया, जिसे तत्काल रिट याचिका दायर करके चुनौती दी गई है।

3. जैसा कि आदेश से स्पष्ट है, रिट याचिकाकर्ता का यह स्वीकृत मामला है कि वित्तीय तंगी के कारण, लीज लाइसेंस की शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया है और इस प्रकार, उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है कि लीज लाइसेंस क्यों न समाप्त कर दिया जाए।

4. रिट याचिकाकर्ता का तर्क है कि बेशक लीज डीड/लाइसेंस की शर्तों का पालन नहीं किया गया है और खनन बकाया भी नहीं चुकाया गया है, जिसकी मांग अतिरिक्त रॉयल्टी के रूप में की गई थी, क्योंकि याचिकाकर्ता के साथ दुर्घटना हुई थी और वह इसे जमा करने की स्थिति में नहीं था, हालांकि, इसे ब्याज सहित नियत तिथि के बाद जमा किया गया है। लेकिन, इस बीच, लीज लाइसेंस समाप्त कर दिया गया था, इसलिए रिट याचिकाकर्ता ने लीज लाइसेंस समाप्त करने के प्राधिकरण के फैसले पर सवाल उठाते हुए पुनरीक्षण प्राधिकारी के समक्ष पुनरीक्षण दायर किया है, लेकिन पुनरीक्षण प्राधिकारी ने इस आधार पर उक्त निर्णय में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है कि बेशक लीज डीड/लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन किया गया है और बकाया भी नहीं चुकाया गया है।

5. रिट याचिका इस आधार पर दायर की गई है कि चूंकि रिट याचिकाकर्ता की स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया था, जिसकी मांग ब्याज सहित अतिरिक्त रॉयल्टी के रूप में की गई थी, तथापि, उसका भुगतान कर दिया गया है, लेकिन उपरोक्त तथ्य पर विचार किए बिना पुनरीक्षण प्राधिकारी ने लीज लाइसेंस की समाप्ति पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिए गए निर्णय में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है, ऐसे में उक्त आदेश न्यायसंगत और उचित नहीं कहा जा सकता है।

6. आगे यह भी दलील दी गई है कि लीज 04.03.2016 से 04.03.2026 तक प्रभावी था।

7. आधार यह लिया गया है कि उक्त निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियम, 2004 के नियम 27(2) के तहत निर्धारित सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना लीज लाइसेंस को समाप्त करने का निर्णय लिया गया था।

8. जबकि दूसरी ओर विद्वान सुश्री सुरभि, ए.सी से ए.ए.जी-II ने संशोधन प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश का बचाव किया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि संशोधन प्राधिकरण की ओर से लीज़ लाइसेंस को समाप्त करने के निर्णय में हस्तक्षेप करने से इनकार करते समय कोई त्रुटि नहीं है क्योंकि लीज़ डीड/समझौते की शर्तों और शर्तों का उल्लंघन किया गया है और साथ ही उन बकाया राशियों का भी उल्लंघन किया गया है जिनका भुगतान याचिकाकर्ता कानूनी रूप से करने के लिए उत्तरदायी है।

9. याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत किए गए तर्क का जवाब देते हुए यह तर्क दिया गया है कि उसे अवसर नहीं दिया गया। तर्क दिया गया है कि रिट याचिकाकर्ता को दो बार कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे और जवाब भी दिया गया था जिसमें रिट याचिकाकर्ता ने बकाया राशि का भुगतान न करने का कारण बताते हुए स्वीकार किया है, यानी रिट याचिकाकर्ता के साथ दुर्घटना हो गई है, इसलिए वह भुगतान करने की स्थिति में नहीं है।

10. यह प्रस्तुत किया गया है कि जब रिट याचिकाकर्ता का यह स्वीकृत मामला है कि पट्टा विलेख/अनुबंध की शर्तों का पालन नहीं किया गया है और केवल सहानुभूति के आधार पर, पुनरीक्षण प्राधिकारी के समक्ष पुनरीक्षण दायर करके लीज लाइसेंस की समाप्ति के निर्णय को रद्द करने की मांग की गई है, जो कोई आधार नहीं हो सकता है, क्योंकि जब रिट याचिकाकर्ता ने एक समझौता किया था, जिसमें नियम और शर्तें थीं, तो रिट याचिकाकर्ता पर उनका सख्ती से पालन करना आवश्यक था।

11. यह तर्क दिया गया है कि चूंकि रिट याचिकाकर्ता का यह स्वीकार किया गया मामला है कि लीज डीड/समझौते की शर्तों का पालन नहीं किया गया है, इसलिए यदि ऐसी परिस्थितियों में प्राधिकरण ने लीज डीड को समाप्त कर दिया है, तो इसे अन्यायपूर्ण निर्णय नहीं कहा जा सकता।

12. जहां तक नियम 2004 के नियम 27(2) की प्रयोज्यता का संबंध है, यह प्रस्तुत किया गया है कि इसका कड़ाई से पालन किया गया है।

13. राज्य के विद्वान वकील ने उपरोक्त प्रस्तुतियों के आधार पर प्रस्तुत किया है कि चूंकि उत्प्रेषण रिट जारी करने के लिए प्रार्थना की गई है और रिट याचिकाकर्ता आदेश के संबंध में कोई त्रुटि इंगित करने में विफल रहा है,

इसलिए यह ऐसा मामला नहीं है जहां उत्प्रेषण रिट जारी करने के लिए दिए गए आदेश में हस्तक्षेप दर्शाकर रिट याचिका पर विचार किया जाना चाहिए।

14. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है, अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया है तथा आक्षेपित आदेश में पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा दर्ज निष्कर्ष का भी अवलोकन किया है।

15. इसमें यह उल्लेख करना आवश्यक है कि मामले को नए सिरे से दाखिल करने के लिए शीर्षक के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है।

16. राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय की मांग नहीं की है, इसलिए पक्षकारों की सहमति से, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर इस रिट याचिका का निपटारा किया जा रहा है।

17. रिट याचिकाकर्ता का यह स्वीकार किया गया मामला है कि रिट याचिकाकर्ता और सक्षम प्राधिकारी के बीच जिन नियमों और शर्तों पर सहमति बनी थी, उनका पालन नहीं किया गया है, क्योंकि रिट याचिकाकर्ता द्वारा ब्याज सहित अतिरिक्त रॉयल्टी के रूप में बकाया राशि का भुगतान समय पर नहीं किया गया है।

18. रिट याचिकाकर्ता ने संबंधित अधिकारी को कारण बताया है कि रिट याचिकाकर्ता दुर्घटना का शिकार हो गया था, जिसके कारण वह समय पर भुगतान करने की स्थिति में नहीं था। हालांकि, देय राशि का भुगतान ब्याज सहित नियत तिथि के बाद किया गया।

19. रिट याचिकाकर्ता ने बकाया राशि का भुगतान ब्याज सहित कर दिया है, लेकिन प्राधिकरण ने उपरोक्त तथ्य पर विचार किए बिना ही लीज लाइसेंस को समाप्त कर दिया है, इसलिए, संशोधन को वैधानिक पुनरीक्षण प्राधिकरण, यानी खान आयुक्त, रांची के समक्ष पेश किया गया।

20. पुनरीक्षण प्राधिकरण ने लीज समाप्त करने के निर्णय में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है, क्योंकि इसमें लीज की शर्तों का पालन नहीं किया गया है, तथा इस आधार पर भी कि लीज समाप्त करने का निर्णय कानूनी प्रक्रिया का पालन करने तथा रिट याचिकाकर्ता को अपना बचाव करने का उचित अवसर देने के बाद लिया गया था।

21. यह भी आधार लिया गया है कि नियम, 2004 के नियम 27(2) का पालन नहीं किया गया है।

22. हमने उक्त नियम का अध्ययन किया है और पाया है कि इसमें प्रावधान किया गया है कि कोई भी निर्णय लेने से पहले याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है।

23. हमने इसमें संलग्न दस्तावेज का भी अध्ययन किया है, जिसमें पाया गया है कि रिट याचिकाकर्ता को दो बार कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और समय के भीतर बकाया राशि का भुगतान न करने का आधार/कारण लेते हुए इसका जवाब भी दिया गया था।

24. जिस क्षण कारण बताओ नोटिस का जवाब दिया गया और लीज समझौते के नियमों और शर्तों के गैर-अनुपालन के तथ्य को रिट याचिकाकर्ता द्वारा स्वीकार कर लिया गया, तब प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन न करने या नियमों के नियम 27(2) के तहत किए गए निर्धारण का पालन न करने का मुद्दा, हमारे सुविचारित दृष्टिकोण के अनुसार, इस कारण से निरर्थक हो जाएगा कि ऐसा जवाब लीज समझौते के नियमों और शर्तों के गैर-अनुपालन के संबंध में रिट याचिकाकर्ता की ओर से स्वीकृति है।

25. कानून में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने के लिए कारण बताओ नोटिस द्वारा अवसर प्रदान करने का मुद्दा केवल उस मामले में है जहां संबंधित पक्ष द्वारा तथ्यों पर विवाद किया जाता है जिसके खिलाफ प्रतिकूल निर्णय लिया जाना है। यदि तथ्य विवादित नहीं है और भले ही मामले को संबंधित प्राधिकारी के समक्ष वापस भेजकर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन न करने के आधार पर तय किया जाएगा, यह एक खाली औपचारिकता और निरर्थक अभ्यास के अलावा और कुछ नहीं होगा। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एस्कॉर्ट्स फार्म लिमिटेड बनाम आयुक्त, कुमाऊं मंडल, नैनीताल, उत्तर प्रदेश और अन्य, (2004) 4 एससीसी 281 में दिए गए निर्णय का संदर्भ लिया जाना चाहिए, जिसमें पैराग्राफ संख्या 64 में यह माना गया है जो इस प्रकार है:

> **"64.** किसी आवश्यक पक्ष को सुनवाई का अधिकार एक मूल्यवान अधिकार है। ऐसे अधिकार से वंचित करना निर्धारित वैधानिक प्रक्रिया

> का गंभीर उल्लंघन है और प्राकृतिक न्याय के नियमों का उल्लंघन है। भूमि के धारक और कुछ अन्य हस्तांतरित व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत इन अपीलों में, हमने पाया है कि सरकारी अनुदान की शर्तें अनुदानकर्ता के रूप में राज्य की अनुमति के बिना भूमि के हस्तांतरण की अनुमति नहीं देती हैं। इसलिए, जिन हस्तांतरित व्यक्तियों की सुनवाई नहीं हुई है, उनके मामलों को वापस भेजना कोई कानूनी परिणाम नहीं देगा, खासकर तब, जब इस कानूनी प्रश्न पर सभी प्रभावित पक्षों को उच्च न्यायालय के समक्ष और इस अपील में इस न्यायालय के समक्ष सुनवाई का पूरा अवसर मिला है। प्राकृतिक न्याय के नियमों का पालन पर्याप्त न्याय करने के लिए किया जाना चाहिए, न कि गुण-दोष के आधार पर मामले के निर्णय में किसी भी बदलाव की संभावना के बिना सुनवाई की रस्म पूरी करने के लिए। हमारे द्वारा ऊपर बताई गई कानूनी स्थिति को देखते हुए, इसलिए, हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन मामलों को वापस भेजने से परहेज करते हैं।"

इसके अलावा, **धर्मपाल सत्यपाल लिमिटेड बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क उपायुक्त, गुवाहाटी एवं अन्य, (2015) 8 एससीसी 519** में उनके माननीय न्यायाधीशों ने पैराग्राफ-39 पर निर्णय दिया है, जिसे निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया जा रहा है:

> **"39.** वर्तमान मामले में हम इन पहलुओं से चिंतित नहीं हैं क्योंकि यह मुद्दा कार्रवाई करने से पहले नोटिस देने से संबंधित है। इस बात पर जोर देते हुए कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को स्ट्रेटजैकेट फॉर्मूले में लागू नहीं किया जा सकता है, उपरोक्त उदाहरण दिए गए हैं। हमने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने के न्यायशास्त्रीय आधार पर प्रकाश डाला है जो प्रक्रियात्मक निष्पक्षता, सामान्य सामाजिक लक्ष्यों की ओर ले जाने वाले परिणाम की सटीकता आदि के सिद्धांत पर आधारित हैं। फिर भी, ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती हैं जहाँ किसी कारण से - शायद इसलिए कि व्यक्ति के खिलाफ सबूत पूरी तरह से सम्मोहक माने जाते हैं - यह महसूस किया जाता है कि निष्पक्ष सुनवाई से "कोई फर्क नहीं पड़ेगा" - जिसका अर्थ है कि सुनवाई से निर्णयकर्ता द्वारा पहुँचे गए अंतिम निष्कर्ष में कोई बदलाव नहीं आएगा।"

26. हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून की स्थापित स्थिति के आधार पर इस मामले पर विचार किया है, जैसा कि ऊपर उल्लेख

किया गया है, तथा रिट याचिकाकर्ता के उत्तर पर भी विचार किया है, जिसमें उसने स्वीकार किया है कि उसने लीज की शर्तों का उल्लंघन किया है।

27. हालाँकि, इसका कारण यह बताया गया है कि वह बकाया राशि का भुगतान करने की स्थिति में नहीं थे।

28. इस न्यायालय का विचार है कि चाहे जो भी कारण हो, यदि वैधानिक प्राधिकारी ने लीज की शर्तों और नियमों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया है, तो सहानुभूति/दया पर आधारित कारण निरर्थक होगा, क्योंकि लीज करने के कारण, उसमें निहित शर्तें और नियम पक्षकारों को बाध्य करते हैं।

29. यदि उच्च न्यायालय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए इसमें ढील देगा, तो यह समझौते की शर्तों और नियमों को फिर से लिखने के अलावा और कुछ नहीं होगा, जो कि अस्वीकार्य है, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **संघ शासित प्रदेश पांडिचेरी और अन्य बनाम पी.वी. सुरेश और अन्य, (1994) 2 एससीसी 70** में कहा है। उपर्युक्त निर्णय के पैराग्राफ 11 में यह माना गया है कि न्यायालय के पास पक्षों के बीच अनुबंध की शर्तों को बदलने या उसे फिर से लिखने का कोई अधिकार नहीं है। पैराग्राफ 11 को नीचे उद्धृत किया गया है:

> **"11.** इस मामले की परिस्थितियों में, हमारी जांच इस प्रश्न तक सीमित है कि क्या अनुबंध इस तरह से बनाया गया था कि इसमें नुकसान अंतर्निहित और निहित था; यदि ऐसा है, तो इसे संशोधित किया जाना चाहिए। अन्यथा, न्यायालय के पास पक्षों के बीच शर्तों को बदलने या अनुबंध को फिर से लिखने का कोई अधिकार नहीं है।

30. उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर न्यायालय का यह मत है कि यदि पुनरीक्षण प्राधिकारी ने खनन पट्टा लाइसेंस समाप्त करते समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिए गए निर्णय में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है, तो हमारे सुविचारित मत के अनुसार, इसमें कोई त्रुटि नहीं कही जा सकती।

31. तदनुसार, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि यह ऐसा मामला नहीं है, जिसमें उत्प्रेषण रिट जारी की जानी है, क्योंकि अभिलेख में कोई त्रुटि स्पष्ट नहीं है, जिस पर उच्च न्यायालय द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उत्प्रेषण रिट जारी करने की शक्ति का प्रयोग करते हुए विचार किया जाना सर्वोपरि है, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने

सैयद याकूब बनाम राधाकृष्णन, ए.आई.आर. 1964 एस.सी. 477 में माना है। उक्त निर्णय का पैराग्राफ संख्या 7 निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया जा रहा है:

> "अनुच्छेद 226 के तहत उत्प्रेषण रिट जारी करने में उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र की सीमाओं के बारे में प्रश्न पर इस न्यायालय द्वारा अक्सर विचार किया गया है और इस संबंध में वास्तविक कानूनी स्थिति अब संदेह में नहीं है। उत्प्रेषण रिट निचली अदालतों या न्यायाधिकरणों द्वारा किए गए अधिकार क्षेत्र की त्रुटियों को सुधारने के लिए जारी की जा सकती है: ये ऐसे मामले हैं जहाँ निचली अदालतों या न्यायाधिकरणों द्वारा अधिकार क्षेत्र के बिना या उससे अधिक या अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में विफलता के परिणामस्वरूप आदेश पारित किए जाते हैं। इसी तरह एक रिट तब भी जारी की जा सकती है जब उसे दिए गए अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए न्यायालय या न्यायाधिकरण अवैध या अनुचित तरीके से कार्य करता है, उदाहरण के लिए, यह आदेश से प्रभावित पक्ष को सुनवाई का अवसर दिए बिना किसी प्रश्न का निर्णय करता है, या जहाँ विवाद से निपटने में अपनाई गई प्रक्रिया प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। हालाँकि, इसमें कोई संदेह नहीं है कि उत्प्रेषण रिट जारी करने का अधिकार क्षेत्र एक पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र है और इसका प्रयोग करने वाला न्यायालय अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य करने का हकदार नहीं है। इस सीमा का अनिवार्य रूप से यह अर्थ है कि साक्ष्य की सराहना के परिणामस्वरूप अवर न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा प्राप्त तथ्यों के निष्कर्षों को रिट कार्यवाही में फिर से नहीं खोला जा सकता है या उन पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। रिकॉर्ड पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली विधि की त्रुटि को रिट द्वारा ठीक किया जा सकता है, लेकिन तथ्य की त्रुटि को नहीं, चाहे वह कितनी भी गंभीर क्यों न प्रतीत हो। न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किए गए तथ्य के निष्कर्ष के संबंध में, उत्प्रेषण रिट जारी की जा सकती है यदि यह दर्शाया जाता है कि उक्त निष्कर्ष को दर्ज करते समय न्यायाधिकरण ने स्वीकार्य और भौतिक साक्ष्य को स्वीकार करने से गलती से इनकार कर दिया था, या अस्वीकार्य साक्ष्य को गलती से स्वीकार कर लिया था जिसने आपत्तिजनक निष्कर्ष को प्रभावित किया है। इसी तरह, यदि तथ्य का निष्कर्ष किसी साक्ष्य पर आधारित नहीं है, तो उसे विधि की त्रुटि माना जाएगा जिसे उत्प्रेषण रिट द्वारा ठीक किया जा सकता है। हालांकि, इस श्रेणी के मामलों से निपटने में, हमें हमेशा यह ध्यान में रखना चाहिए कि न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किए गए तथ्य के निष्कर्ष को

इस आधार पर प्रमाणिक रिट की कार्यवाही में चुनौती नहीं दी जा सकती है कि न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत प्रासंगिक और भौतिक साक्ष्य आपत्तिजनक निष्कर्ष को बनाए रखने के लिए अपर्याप्त या अपर्याप्त थे। किसी बिंदु पर दिए गए साक्ष्य की पर्याप्तता या पर्याप्तता और उक्त निष्कर्ष से निकाले जाने वाले तथ्य का अनुमान न्यायाधिकरण के अनन्य अधिकार क्षेत्र में है, और उक्त बिंदुओं को रिट कोर्ट के समक्ष नहीं उठाया जा सकता है। यह इन सीमाओं के भीतर है कि अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालयों को अधिकार क्षेत्र प्रदान किया गया है। 226 के तहत उत्प्रेषण रिट जारी करने का प्रयोग वैध रूप से किया जा सकता है (देखें हरि विष्णु कामथ बनाम अहमद इशाक, 1955-1 एससीआर 1104 : ((एस) एआईआर 1955 एससी 233); नागेन्द्र नाथ बनाम हिल्स डिवीजन के कमिश्नर, 1958 एससीआर 1240 : (एआईआर 1958 एससी 398) और कौशल्या देवी बनाम बचित्तर सिंह, एआईआर 1960 एससी 1168

हरि विष्णु कामथ बनाम अहमद इशाक एवं अन्य, एआईआर 1955 सुप्रीम कोर्ट 233 में, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पैराग्राफ संख्या 21 में निम्नानुसार निर्णय दिया है:

"उत्प्रेषण रिट के चरित्र और दायरे तथा जिन शर्तों के तहत इसे जारी किया जा सकता है, के संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव स्थापित माने जा सकते हैं: (1) उत्प्रेषण रिट अधिकार क्षेत्र की त्रुटियों को सुधारने के लिए जारी की जाएगी, जैसे कि जब कोई अवर न्यायालय या न्यायाधिकरण अधिकार क्षेत्र के बिना या उससे अधिक कार्य करता है, या इसका प्रयोग करने में विफल रहता है। (2) उत्प्रेषण रिट तब भी जारी की जाएगी जब न्यायालय या न्यायाधिकरण अपने निस्संदेह अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में अवैध रूप से कार्य करता है, जैसे कि जब वह पक्षों को सुनवाई का अवसर दिए बिना निर्णय लेता है, या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। (3) उत्प्रेषण रिट जारी करने वाला न्यायालय पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में कार्य करता है, न कि अपीलीय अधिकार क्षेत्र के। इसका एक परिणाम यह है कि न्यायालय अवर न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा प्राप्त तथ्यों की समीक्षा नहीं करेगा, भले ही वे गलत हों। यह इस सिद्धांत पर है कि जिस न्यायालय के पास किसी विषय-वस्तु पर क्षेत्राधिकार होता है, उसके पास गलत के साथ-साथ सही का भी निर्णय करने का क्षेत्राधिकार होता है, और जब विधानमंडल उस निर्णय के विरुद्ध अपील का अधिकार प्रदान नहीं करना चाहता, तो यह उसके उद्देश्य और नीति को पराजित करेगा, यदि कोई उच्च न्यायालय साक्ष्य के

आधार पर मामले की पुनः सुनवाई करे और उत्प्रेषणात्मक रूप में अपने स्वयं के निष्कर्षों को प्रतिस्थापित करे।"

सावर्ण सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य, (1976) 2 एससीसी 868 में, उनके माननीय न्यायाधीशों ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत प्रमाण पत्र जारी करने की शक्ति पर चर्चा करते हुए, पैराग्राफ संख्या 12 और 13 में निम्नानुसार निर्णय दिया है:

> **"12.** प्रस्तुत विवादों से निपटने से पहले, यह ध्यान रखना उपयोगी होगा कि उत्प्रेषण अधिकार क्षेत्र की सीमाओं को इंगित करने वाले सामान्य सिद्धांतों का प्रयोग केवल निचली अदालतों या न्यायाधिकरणों द्वारा किए गए अधिकार क्षेत्र की त्रुटियों को सुधारने के लिए किया जा सकता है। उत्प्रेषण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग केवल पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में ही जारी किया जा सकता है जो अपीलीय अधिकार क्षेत्र से अलग है। अनुच्छेद 226 के तहत विशेष अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाला न्यायालय अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य करने का हकदार नहीं है। जैसा कि इस न्यायालय ने सैयद याकूब के मामले (सुप्रा) में बताया था
>
> **13.** किसी अवर न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किए गए तथ्य के निष्कर्ष के संबंध में, उत्प्रेषण रिट केवल तभी जारी की जा सकती है जब ऐसे निष्कर्ष को दर्ज करते समय न्यायाधिकरण ने ऐसे साक्ष्य पर काम किया हो जो कानूनी रूप से अस्वीकार्य हो, या उसने स्वीकार्य साक्ष्य को स्वीकार करने से इनकार कर दिया हो, या यदि निष्कर्ष किसी भी साक्ष्य द्वारा समर्थित न हो, क्योंकि ऐसे मामलों में त्रुटि कानून की त्रुटि के बराबर होती है। रिट क्षेत्राधिकार केवल उन मामलों तक ही सीमित है जहां अवर न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर या उनके द्वारा निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से इनकार करने के परिणामस्वरूप आदेश पारित किए जाते हैं या वे अपने अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में अवैध या अनुचित तरीके से कार्य करते हैं जिससे न्याय की गंभीर विफलता होती है।"

हेंज इंडिया (पी) लिमिटेड एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, (2012) 5 एससीसी 443 में उनके माननीय न्यायाधीशों ने पैराग्राफ संख्या 66 और 67 में निम्नानुसार निर्णय दिया है:

> **"66.** न्यायिक समीक्षा की शक्ति के प्रयोग से निपटने वाला न्यायालय विधानमंडल या कार्यपालिका या उनके प्रतिनिधियों के निर्णय के स्थान पर अपने निर्णय को प्रतिस्थापित नहीं करता है, तथा न्यायालय अपने स्वयं के समीक्षा द्वारा "विशेषज्ञ की भावना" को प्रतिस्थापित नहीं करता है, यह भी इस न्यायालय के निर्णयों द्वारा काफी हद तक स्थापित है। ऐसे सभी मामलों में न्यायिक जांच केवल यह पता लगाने तक सीमित है कि क्या तथ्यों के निष्कर्षों का साक्ष्य पर उचित आधार है और क्या ऐसे निष्कर्ष देश के कानूनों के अनुरूप हैं।
>
> **67.** धरंगधर केमिकल वर्क्स लिमिटेड बनाम सौराष्ट्र राज्य में इस न्यायालय ने माना कि तथ्य के किसी प्रश्न पर न्यायाधिकरण का निर्णय, जिसे निर्धारित करने का अधिकार उसके पास है, संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत कार्यवाही में तब तक प्रश्नगत नहीं किया जा सकता जब तक कि यह किसी साक्ष्य द्वारा पूरी तरह से समर्थित न हो। इसी प्रभाव के लिए इस न्यायालय ने थानसिंह नाथमल मामले में अपनाए गए दृष्टिकोण को अपनाया, जहां इस न्यायालय ने माना कि उच्च न्यायालय आम तौर पर ऐसे प्रश्नों का निर्धारण नहीं करता है, जिनके लिए रिट का दावा किए जाने वाले प्रवर्तन के अधिकार को स्थापित करने के लिए साक्ष्य की विस्तृत जांच की आवश्यकता होती है।

थानसिंह बनाम कर अधीक्षक, ए.आई.आर. 1964 1419 सुप्रीम कोर्ट में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है कि उच्च न्यायालय संयुक्त रूप से उस प्रश्न का निर्धारण नहीं करता है जिसके लिए उस अधिकार को स्थापित करने के लिए साक्ष्य की विस्तृत जांच की आवश्यकता होती है जिसके लिए रिट का दावा किया जाता है।

पेप्सिको इंडिया होल्डिंग (पी) लिमिटेड बनाम कृष्ण कांत पांडे, (2015) 4 एससीसी 270 में, उनके माननीय न्यायाधीशों ने न्यायाधिकरण के निष्कर्ष में हस्तक्षेप के मामले में भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के दायरे पर चर्चा करते हुए, चंदावरकर सीता रत्न राव बनाम आशालता एस. गुरम, (1986) 4 एससीसी 447 के पैरा-17 में दिए गए निर्णय पर भरोसा करते हुए निम्नानुसार निर्णय दिया है:

"17. तथ्यों के पाए जाने की स्थिति में न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। बथुतमल रायचंद ओसवाल बनाम लक्ष्मीबाई आर. तर्ता मामले में इस न्यायालय की टिप्पणियों का संदर्भ लिया जा सकता है, जहां इस न्यायालय ने कहा था कि उच्च न्यायालय अनुच्छेद 227 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने की आड़ में खुद को अपील न्यायालय में नहीं बदल सकता, जब विधायिका ने अपील का अधिकार प्रदान नहीं किया है। उच्च न्यायालय साक्ष्य की जांच करके और फिर से मूल्यांकन करके तथ्यों की त्रुटियों को ठीक करने में सक्षम नहीं था। न्यायालय की ओर से बोलते हुए, न्यायमूर्ति भगवती, जो उस समय विद्वान मुख्य न्यायाधीश थे, ने रिपोर्ट के पृष्ठ 1301 पर निम्नलिखित टिप्पणी की:

अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत विशेष सिविल आवेदन निस्संदेह अनुच्छेद 227 के तहत एक आवेदन था और इसलिए, उस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के दायरे और दायरे पर विचार करना ही महत्वपूर्ण है। क्या उच्च न्यायालय के पास अनुच्छेद 227 के तहत एक आवेदन में जिला न्यायालय द्वारा प्राप्त तथ्यों के निष्कर्षों को बाधित करने का अधिकार था? वरयाम सिंह बनाम अमरनाथ में इस न्यायालय के निर्णय से यह अच्छी तरह से स्थापित है कि
..... अनुच्छेद 227 द्वारा प्रदत्त अधीक्षण की शक्ति, जैसा कि हैरिस, सी.जे. द्वारा डालमिया जैन एयरवेज बनाम सुकुमार मुखर्जी में बताया गया है, का प्रयोग अत्यंत संयमित रूप से और केवल उचित मामलों में किया जाना चाहिए ताकि अधीनस्थ न्यायालयों को उनके अधिकार की सीमाओं के भीतर रखा जा सके, न कि केवल त्रुटियों को सुधारने के लिए।

कानून के इस कथन को नागेंद्र नाथ बोस बनाम हिल्स डिवीजन के कमिश्नर मामले में इस न्यायालय के बाद के निर्णय में अनुमोदन के साथ उद्धृत किया गया था और न्यायमूर्ति सिन्हा द्वारा, जैसा कि वे उस समय उस मामले में न्यायालय की ओर से बोलते हुए थे, इस ओर ध्यान दिलाया गया था:

इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत न्यायिक या अर्ध-न्यायिक प्रकृति के आदेशों के साथ न्यायिक

हस्तक्षेप की शक्तियाँ संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्ति से अधिक नहीं हैं। अनुच्छेद 226 के तहत हस्तक्षेप की शक्ति रिकॉर्ड पर स्पष्ट गलती के आधार पर किसी विवादित आदेश को रद्द करने तक सीमित हो सकती है। लेकिन संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत हस्तक्षेप की शक्ति न्यायाधिकरण से उसके अधिकार की सीमाओं के भीतर काम करने की मांग करने तक सीमित है।

महाप्रबंधक, इलेक्ट्रिकल रेंगाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, उड़ीसा एवं अन्य बनाम गिरिधारी साहू एवं अन्य, (2019) 10 एससीसी 695 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय द्वारा प्रमाण पत्र जारी करने के दायरे के मुद्दे पर गहनता से विचार किया है और निर्धारित किया है कि यदि न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण और दुराग्रह पर आधारित है, तो आदेश को रद्द/रद्द किया जाना उचित है।

32. तथ्यात्मक पहलू के साथ-साथ विधिक स्थिति पर विचार-विमर्श करने के पश्चात न्यायालय का यह मत है कि यह ऐसा मामला नहीं है, जिसमें आरोपित आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप दर्शाने की आवश्यकता है।

33. तदनुसार, तत्काल रिट याचिका विफल हो जाती है और खारिज की जाती है।

34. यदि कोई लंबित अंतरिम आवेदन है तो उसका भी निपटारा हो गया है।

(न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद)

(न्यायमूर्ति नवनीत कुमार)

सौरभ/-ए.एफ.आर.

यह अनुवाद सुश्री लीना मुखर्जी, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।